भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2881
दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृतसर में सीवरेज प्रणाली का उन्नयन

†2881. श्री गुरजीत सिंह औजलाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा अमृतसर के निवासियों और आगंतुकों को आपूरित पेयजल में सीवेज के मिश्रण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ख) अमृतसर शहर में पेयजल की गुणवत्ता और समग्र स्वच्छता में सुधार के लिए सभी सीवेज प्रणालियों को उन्नत करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) वैश्विक पर्यटन स्थल होने के कारण अमृतसर में स्वच्छता और जल प्रबंधन को बढ़ाने के लिए की गई विशिष्ट पहल और किए गए/किए जा रहे बजटीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को दिनांक 25 जून 2015 को चयनित 500 शहरों (एकीकृत किए गए 15 शहरों सहित 485 शहरों) और कस्बों में शुरू किया गया था। मिशन चयनित शहरों और कस्बों में बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है; जल आपूर्ति के क्षेत्र सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; वर्षा जल निकास; हरित क्षेत्र और उद्यान; और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन शामिल हैं। इस मिशन में शहरी सुधारों और क्षमता निर्माण का एक संग्रह शामिल किया गया है।

अमृत के तहत, अमृतसर शहर ने 89.36 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाएं शुरू की हैं जिनमें 75.03 करोड़ रुपये की लागत वाली 5 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 13.34 करोड़ रुपये

की लागत से एक सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजना और 0.99 करोड़ रुपये की 4 उद्यान परियोजनाएं शामिल हैं। अमृत और कन्वर्जेंस के तहत 54,377 पानी के नल कनेक्शन और 4,048 सीवर कनेक्शन (मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) के माध्यम से शामिल किए गए घरों सहित) प्रदान किए गए हैं।

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) 2.0 योजना दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को सभी यूएलबी/शहरों में शुरू की गई है, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन गए हैं। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। जल निकायों का पुनरुद्धार, हरित क्षेत्रों और उद्यानों का विकास तथा जल के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी उप-मिशन मिशन के अन्य घटक हैं। अमृत 2.0 के लिए कुल लक्षित परिव्यय 2,77,000 करोड़ रुपये है, जिसमें पांच वर्ष के लिए 76,760 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।

अमृत 2.0 के तहत, अब तक अमृतसर जिले में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 213.29 करोड़ रुपये मूल्य की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 102.89 करोड़ रुपये मूल्य की 7 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 110.4 करोड़ रुपये मूल्य की एक सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजना शामिल है। 25.99 एमएलडी जल शोधन संयंत्र क्षमता के वृद्धि/संवर्धन हेतु अनुमोदित किया गया है।

अमृत और अमृत 2.0 के तहत निधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित/जारी की जाती हैं न कि जिला/शहरी स्थानीय निकायों/क्षेत्र-वार आधार पर, इसके अतिरिक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर जिलों/शहरी स्थानीय निकायों को निधियां जारी करते हैं।

पंजाब में अमृत के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए 1,204.47 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता (सीए) की प्रतिबद्धता की तुलना में 1,190.77 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पंजाब में अमृत 2.0 के तहत, परियोजनाओं के लिए 1,596.29 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता (सीए) की तुलना में, 254.69 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

*****